बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 28/12/16

संख्या–7/मुक0–08–1/2015(खंड I)सा0प्र0 17282/भारत–संविधान के अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना से परामर्श के पश्चात्, विभागीय अधिसूचना संख्या–7/ए0–1–210/2000 का0 6069 दिनांक 25.06.2009 द्वारा संशोधित एवं अधिसूचित नियमों का अधिक्रमण करते हुए बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:–

बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।–** (1) यह नियमावली बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

   (2) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा और उन रिक्तियों पर भी प्रभावी होगा, जो अभी भरी जानी है।

2. **बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 में नियम–4(क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–**

4क– सीधी भर्ती में आरक्षण:–

(i) **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती हेतु सभी रिक्तियाँ भरी जायेंगी:–**

(क) खुली गुणागुण कोटि से – 50 प्रतिशत

(ख) आरक्षित कोटि से – 50 प्रतिशत

(ii) आरक्षित श्रेणी के विरूद्ध 50 प्रतिशत रिक्तियों में अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशत, अत्यंत पिछडा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत यथा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तिओं में आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम, 1991 (समय–समय पर यथा संशोधित) में वर्णित है।

(iii) सभी कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत तथा अस्थि विकलांगों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से उनके लिये आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिये सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में अगली चयन प्रक्रिया तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाये रखा जायेगा और यदि अगले वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायेगा और विनिमय पूरित रिक्तियाँ उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेंगी ।

(v) अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में अगली चयन प्रक्रिया तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाये रखा जायेगा और यदि अगले वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो तो यह रिक्तियाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेंगी और विनिमय द्वारा पूरित रिक्तियाँ उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेंगी।

(vi) यदि तृतीय चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की संख्या, विनिमय फॉर्मूला के बाद भी उनके लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है तो तृतीय चयन प्रक्रिया में शेष पूर्वागत (बैक लॉग) रिक्तियाँ, सामान्य वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों से, उन्हें अनारक्षित करके भरी जा सकेंगी। किंतु वैसी अनारक्षित रिक्तियाँ अगली तीन चयन प्रक्रियाओं तक अग्रगणित (carry forward) रहेंगी।

3. परिशिष्ट–ग में उपनियम–8 के नीचे निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा:–

"महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

इसी प्रकार महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक सैद्धांतिक पत्र में न्यूनतम अहर्तांक में 5 प्रतिशत की छूट होगी एवं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के न्यूनतम अहर्तांक कुल 45 प्रतिशत होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/मुक0–08–1/2015(खंड I)सा0प्र0 17282 /पटना–15, दिनांक 28/12/16

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department

Notification

Patna-15, Date: 28/12/16

No.-7/Muk.-08-1/2015 (Part I)G.A./17282.../In exercise of the powers conferred by Article 233 of the Constitution of India and in supersession of Rules as amended and notified vide, notification no. 7/a.1-210/2000 ka. 6069 dated 25.06.2009, the Governor of Bihar, in consultation with High Court of Judicature at Patna, is pleased to make the following amendments in the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951:-

The Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2016

1. Short title and commencement:-
   (1) These rules may be called the Bihar Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2016.
   (2) These rules shall come into force at once and shall extend to the vacancies which are yet to be filled up.
2. In the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951, the Rule "4A" shall be substituted by the following:-

"4.A Reservation for Direct Recruitment:-

(i) All vacancies for direct recruitment to the post of Additional District and Sessions judge shall be filled up:-

(a) from open merit category – 50%

(b) from reserved category- 50%

(ii) Against the reserved 50% vacancies, there shall be reservation of 16% for Scheduled Castes, 1% for Scheduled Tribes, 21% for Extremely Backward Class, 12% for Backward Class candidates as defined under the Bihar Reservation of Vacancies in Post and Services (for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes) Act, 1991 as amended from time to time.

(iii) There shall be 35% horizontal reservation for women and 1% horizontal reservation for orthopedically disabled candidates in all categories.

(iv) In case of non-availability of suitable candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for appointment in vacancies reserved for them, the vacancies shall continued to be reserved for them for next selection process, and if suitable candidates are not available even in the second process, the vacancies shall be filled by exchange between the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the vacancies so filled will be treated as reserved for the candidates for that particular community who are actually appointed.

(v) In case of non-availability of suitable candidates from the Extremely Backward Class and Backward Class for appointment in vacancies reserved for them, the vacancies shall continued to be reserved for them for the next selection process, and if suitable candidates are not available even in the second process, the vacancies shall be filled by exchange between the candidates of Extremely Backward Class and Backward Class and the vacancies so filled by exchange shall be treated as reserved for the candidates of that particular community who are actually appointed.

(vi) If in the third selection process, the number of suitable candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Extremely Backward Class and Backward Class are less than the number of vacancies reserved for them even after exchange formula, the remaining backlog vacancies may be filled by suitable general candidates after de-reserving them but the vacancies so de-reserved shall be carried forward for next three selection process."

3. The following proviso to the clause 8 of appendix C shall be added as hereunder:-

"The minimum qualifying marks in the preliminary test would be relaxed for reserved category candidates including women and orthopedically disabled candidates by 5%.

Similarly, there shall be relaxation of 5% marks in each theory paper whereas 45% in aggregate of the written examination and viva voce would be qualifying marks for the reserved category candidates including women and orthopedically disabled candidates."

By the Order of Governor of Bihar

(Dr. Dharmendra Singh Gangwar)
Principal Secretary to the Government

Memo No. 7/Muk.-08-1/2015 (Part I)G.A ..17282../Patna, Dated ..28/12/16.

Copy forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna for publication in forth coming issue of Govt. Gazette.

2. Kindly send 400 (Four hundred) copies to this department.

Principal Secretary to the Government

Memo No. 7/Muk.-08-1/2015 (Part I)G.A .17282.../Patna, Dated ...28/12/16

Copy forwarded to Registrar General, High Court, Patna/Secretary, B.P.S.C., Patna/ Secretary, Law Deptt./Principal Secretary, Cabinet Secretariat in reference to Cabinet Item No.-01 dated 27.12.2016/All District and Session Judge/All Departments/All Head of Departments for information and necessary action.

Principal Secretary to the Government